आकाशवाणी केन्द्र शिमला
10.06.2024 / प्रादेशिक समाचार / 19:45 बजे

मुख्य समाचार

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ गरीबों को आवास देने का लिया निर्णय।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालते ही किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त की जारी– 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा– वर्तमान वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 5 सौ 17 करोड़ रूपये का बजट आंबटित।
- भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल सहित 7 राज्यों में 13 विधानसभा क्षेत्रों के रिक्त स्थानों के लिए उपचुनाव की अनुसूची की जारी।

.....

केंद्रीय मंत्रिमंडल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास में एनडीए थ्री प्वांइट ओ के नए मंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में घर बनाने को अपनी मंजूरी प्रदान की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद भार संभालते ही आज किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त् जारी की है। ये किश्त् नौ करोड 30 लाख किसानों को लगभग बीस हजार करोड रुपये का लाभ पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय, किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार, कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेगी।

विभाग बंटवारा

इस बीच केंद्रीय मंत्री परिषद के लिए विभागों की घोषणा कर दी गई है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जबकि अमित शाह गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री बने रहेंगे। इसी तरह नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त व कॉरपोरेट, मनोहर लाल को शहरी विकास, डॉ

एस जयशंकर विदेश मंत्री, जेपी नड्डा को स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेलवे व सूचना व प्रसारण मंत्रालय दिया गया है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार देश के किसानों, युवाओं, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित है। एक ब्यान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले फैसले में किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की है जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एनडीए सरकार इसी तरह देश के लोगों के विकास के लिए काम करती रहेगी और आने वाले समय में अनेक जनहितकारी फैसले लिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधियों के हौंसले बुलंद है।

इस बीच जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 करोड़ गरीबों को आवास देने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में हिमाचल पथ परिवहन निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिमला में आज निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए 25 नई वॉल्वो बसें और 50 टेंपो ट्रैल्वर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा निगम के बेडे में इलैक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी जिनके प्रापण के लिए प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में इलैक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 5 सौ 17 करोड़ रूपए का बजट आबंटित किया गया है। सुखविंदर सिह सुक्खू ने प्रदेश में सीमित हवाई रेल नेटवर्क के दृष्टिगत लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम के संचालन को सुदृढ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निगम को प्रतिमाह 63 करोड़ रूपए प्रदान करेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में परिहवन सुविधा को सुदृढ करने के साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इलैक्ट्रिक बसों की विशेष भूमिका रहेगी।

सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने निजी लाभ के लिए अपनी सदस्यता को दांव पर लगाया है और आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि

आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्दलीय विधायकों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है जबकि वे किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते थे। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें पांच साल के लिए अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए चुना था लेकिन निजी स्वार्थ के चलते निर्दलीय विधायकों ने राज्य पर उप चुनाव का बोझ डाला है। मुख्यमंत्री ने नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान वे प्रदेश के लिए आपदा राहत पैकेज की मांग भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे।

मनीष गर्ग

भारतीय निर्वाचन आयोग ने सात राज्यों में 13 विधानसभा क्षेत्रों के रिक्त स्थानों के लिए उप–चुनावों की अनुसूची जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में बताया कि बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला के देहरा, हमीरपुर जिला के हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र और सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को उप–चुनाव के लिए मतदान होगा जबकि 13 जुलाई को मतगणना होगी। मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश में उप–चुनावों के लिए राजपत्रित अनुसूची 14 जून, को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 21 जून तय की गई है जबकि 24 जून, को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और 26 जून नामांकन वापिस लेने की अन्तिम तिथि होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15 जुलाई से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संबंधित जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मनीष गर्ग ने इस अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन की महत्तता पर बल दिया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और हितधारकों से निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

शपथ

प्रदेश में उप चुनाव के माध्यम से 14वीं विधान सभा के लिए नव निर्वाचित सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया शपथ दिलाएँगे। यह शपथ समारोह 12 जून को सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय के पुस्तकालय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस उप चुनाव में काँग्रेस पार्टी के 4 जिसमें लाहौल स्पिति से अनुराधा राणा, सुजानपुर से कैप्टन रणजीत सिंह, कुटलैहड़ से विवेक शर्मा और गगरेट से राकेश कालिया शामिल हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य धर्मशाला से सुधीर शर्मा, और बड़सर निर्वाचन क्षेत्र से इन्द्र दत्त लखनपाल, निर्वाचित हुए हैं।

जगत सिंह नेगी

जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पात्र लोगों को नौतोड़ भूमि प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि राज्य में हिमाचल प्रदेश नौतोड भूमि नियम 1968 के तहत 20 बीघा से कम भूमि वाले पात्र लाभार्थियों को 20 बीघा सरकारी भूमि प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत जनजातीय लोगों को लाभान्वित किया गया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के फलस्वरूप प्रदेश में प्रार्थियों को नौतोड़ भूमि आबंटित नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि नौतोड़ के कई मामले अभी भी लंबित पड़े हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों से राज्यपाल से वन संरक्षण अधिनियम 1980 को हटाने का आग्रह किया है ताकि पात्र लाभार्थियों को नौतोड़ भूमि प्रदान की जा सके।

विक्रमादित्य

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी में लोक निर्माण विभाग द्वारा जिले में क्रियान्वित किए जा रहे सीआरएफ, नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण तीन के कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में वर्तमान में तीन सौ 50 करोड़ के कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्रियान्वित किए जा रहे हैं और ये कार्य अगले डेढ़ वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जोगिन्द्रनगर क्षेत्र में सीआरएफ के माध्यम से बन रहे मछयाल पुल के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इसका कार्य पूरा हो सके। लोकनिर्माण मंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान विकास का जो विजन उन्होंने रखा था उसे वे प्रदेश के लोक निर्माण व शहरी विकास विकास मंत्री के तौर पर पूरा करेंगे।

.....